

क,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

दिनांक 13 मार्च, 2013

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं०-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश सं०-607/XXVII(1)/2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-1053/3-5(रा०सै०-वाई०बोर्ड.) दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की आयोजनागत पक्ष की योजना "वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता" में चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) के सापेक्ष शासनादेश संख्या 1137/X-2-2012-12(41)2012 दिनांक 18 जून, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 13.33 लाख शासनादेश संख्या 1975/X-2-2012-12(41)2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 26.67 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु ₹ 20,00,000/- (₹ बीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्तवत् निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद एवं उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु उनकी वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकतानुसार तथा उन पर उपलब्ध धनराशि को समायोजन करते हुये आवंटित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनार्थ एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
 4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
 5. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
 6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
 7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
 8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
 9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय.
 10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
 11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी.
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
 13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1303270163 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
 14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 03-वाइल्ड लाइफ बोर्डों को सहायता के मानक मद 20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

योजना का नाम/मानक मद	बजट प्राविधान	प्रथम अनुपूर्क अनुदान से प्राप्त बजट	आयोजनागत पक्ष का कुल बजट	निर्गत धनराशि	अवशेष बजट	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन						
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-						
110-वन्य जीव परिरक्षण						
वार्ल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता						
20- सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	4000	2000	6000	4000	2000	2000
योग	4000	2000	6000	4000	2000	2000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ बीस लाख मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-186(P)/XXVII(4)/2013 दिनांक 9 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)

अपर सचिव

574
संख्या- (1)/X-2-2013, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

ओझा से,

(मनोज चन्दन)

अपर सचिव

आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर की योजना "वाईल्ड लाइफ बोर्डों को सहायता" में निर्गत वित्तीय स्वीकृति से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण:-

कराये जाने वाला कार्य का विवरण	धनराशि ₹ लाख में
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों हेतु	20.00
योग	20.00

(मनीज चन्द्रन)

अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - S1303270163

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1303270163

आवंटन पत्र दिनांक - 13-Mar-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
110 - वन्य जीवन परिरक्षण 03 - वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता
00 - वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	4000000	2000000	6000000
	4000000	2000000	6000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

2000000

